एक दशक का हिसाब किताब

सामाजिक सुरक्षा

पेंशन

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों की सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही का विचार रही है। मीडिया में विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी अतिशयोक्ति सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देती है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावा

- सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करें
- हम सभी जानते हैं कि जीवन में एक चीज जो निश्चित है वह है जीवन की अनिश्चितता। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती हैं। और यह ताकत अब प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधान मंत्री व्यय वंदना योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंच गई है, " प्रधान मंत्री मोदी ने 2018 में कहा था।

- हमारी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के अपने 'मंत्र' को मजबूत किया। हमारे विकास दर्शन में समावेशिता के सभी तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे की, समाज के सभी वर्गों के कवरेज के माध्यम से सामाजिक समावेशिता - एफएम, बजट भाषण 2024-25

हकीकत:

- पिछले महीने की **नीति आयोग की रिपोर्ट में** कहा गया है कि **भारत में लगभग 78% बुजुर्ग आबादी बिना पेंशन कवर के रहती है** और **लगभग 70% अपने रोजमर्रा के भरण-पोषण के लिए अपने परिवार/रिश्तेदारों पर निर्भर हैं।**

- कमजोर लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। 65 वर्ष से कम उम्र के बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत गैर-अंशदायी पेंशन 2007 से स्थिर बनी हुई है।

- 2012 में **विधवाओं और विकलांगों के लिए 200 रुपये से मात्र 300 रुपये**, ऐसे समय में जब **उड़द दाल की कीमत 138 रुपये प्रति किलोग्राम** और **सरसों के तेल की कीमत 136 रुपये** प्रति किलोग्राम है, पेंशन राशि एक मजाक से ज्यादा नहीं है।

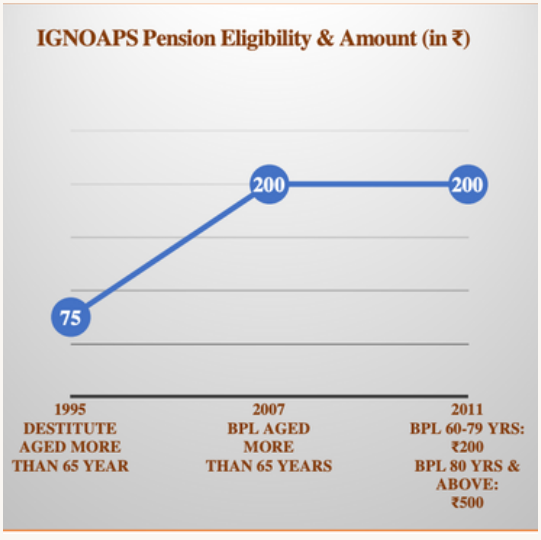

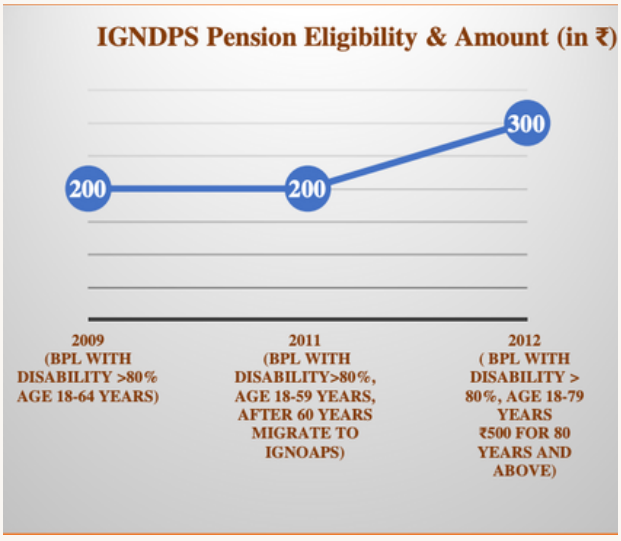

- **कुल बजट परिव्यय के हिस्से के रूप में एनएसएपी के आवंटन में दस वर्षों में लगातार गिरावट आई है, जो 2014-15 में 0.58% से घटकर वर्तमान बजट में मात्र 0.2% रह गई है।** पेंशन के लिए आवंटित राशि लगभग 9500 करोड़ रुपये पर स्थिर बनी हुई है। ध्यान रखें कि केवल 12 बड़े डिफॉल्टर कॉरपोरेट्स को दी गई कुल कटौती 2.84 लाख करोड़ थी।

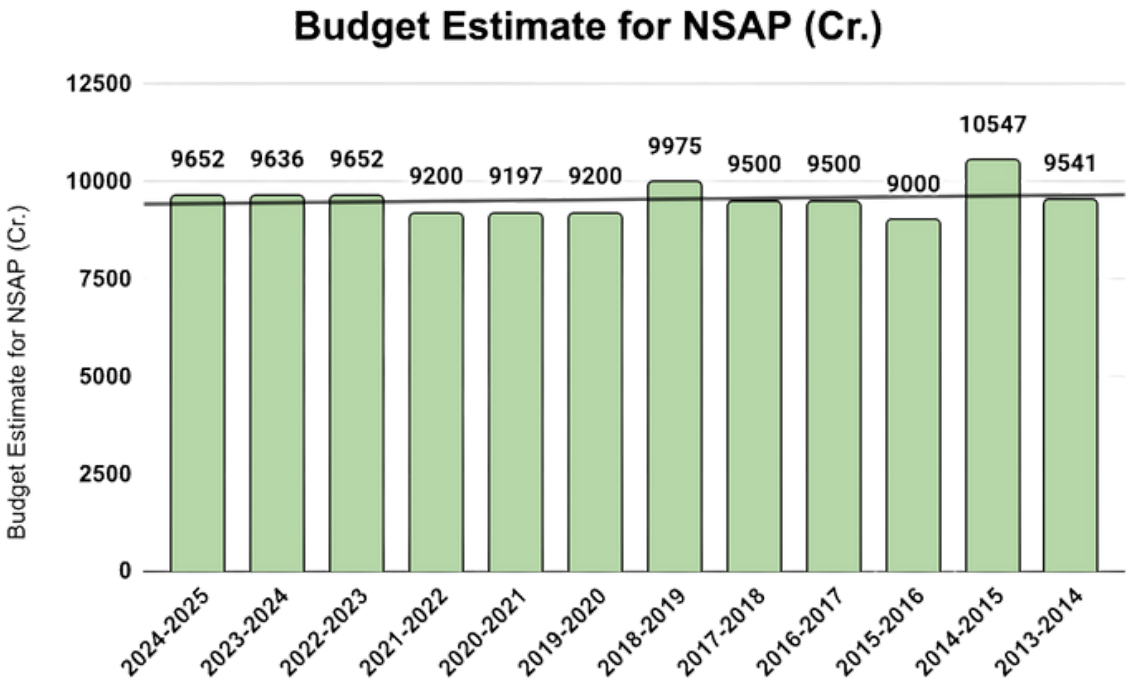

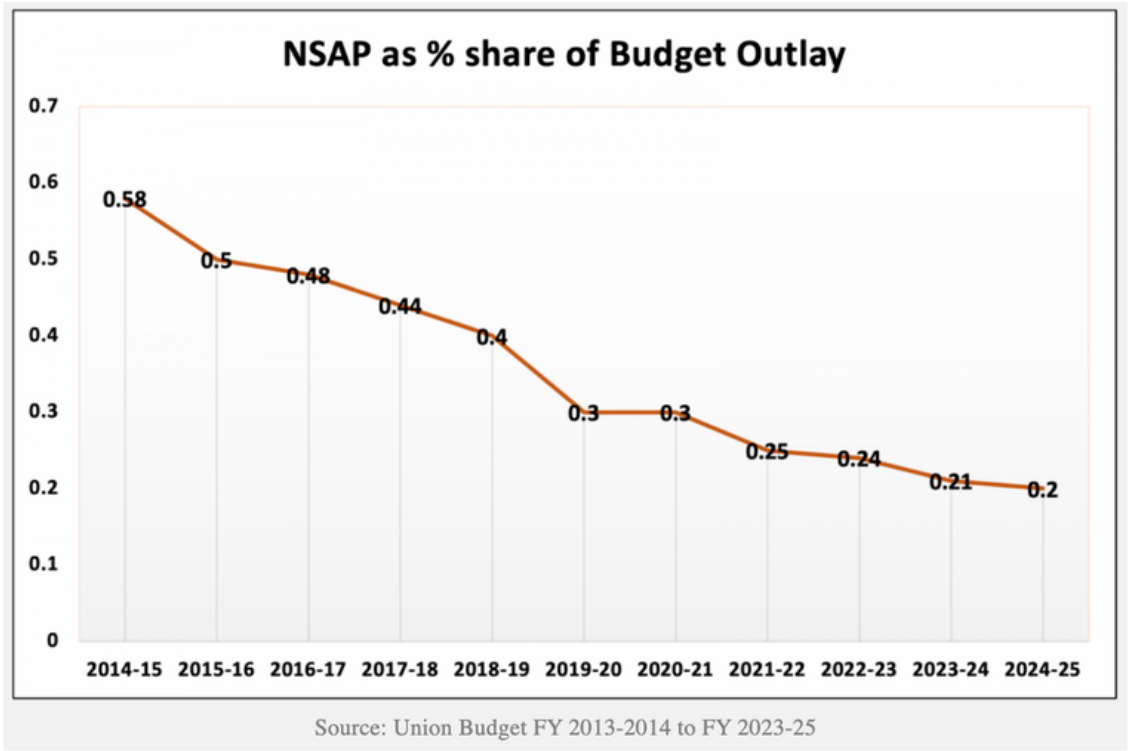

Source: Union Budget FY 2013-2014 to FY 2023-25

- इंडिया एजिंग रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग सब से गरीब संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ बुजुर्ग बिना किसी आय के जीवन यापन करते हैं। इसके बावजूद, वृद्धावस्था योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2012 में 2.27 करोड़ से घटकर 2.21 करोड़ हो गई है।

- कार्यक्रम के तहत कुल कवरेज 2012-13 में 2.48 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2023 में 2.97 करोड़ हो गया है। कड़े पात्रता मानदंडों के कारण योजना को बहिष्कार के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। **पुराने एसईसीसी डेटा, महिलाओं के लिए सख्त आयु मानदंड और विकलांग व्यक्तियों के लिए नामांकन के लिए अत्यधिक उच्च विकलांगता स्तर पर इसकी निर्भरता सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का कारण बन रही है**।

- **योजना के लिए अपर्याप्त धन के कारण, राज्य केंद्र सरकार की तुलना में सामाजिक सुरक्षा सहायता पर 5 से 10 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं।** ऐसा तब है जब केंद्र सरकार के विज्ञापन केवल अपने "लाभार्थियों" को प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री को श्रेय देने का प्रयास करते हैं।

- भाजपा सरकार ने **असंगठित क्षेत्र** के श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के लिए बहुत कम काम किया है, जो भारत के **कार्यबल का 93% हिस्सा** हैं। उन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध पेंशन योजनाओं से बाहर रखा गया है।

- संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 2019 में शुरू की गई अंशदायी वृद्धावस्था योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) का बजट **2023-24 में 350 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में सिर्फ 177 करोड़ रुपये हो गया है**।

- वास्तव में पीएम एसवाईएम 10 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल होने के कारण अप्रभावी साबित हुआ है। **2019 से 2024** के बीच केवल **50 लाख के करीब लोगों ने ही इस योजना में नामांकन कराया** है। **जनवरी और जुलाई 2023** के बीच, नामांकित **लाभार्थियों में से 21% ने कार्यक्रम छोड़** दिया।

- यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी, हमें प्रस्ताव पर शायद ही कुछ मिलता है।

- 18 महीने के डीए एरियर पर कोई फैसला नहीं
-जनविरोधी नई पेंशन योजना को खत्म करने की कोई घोषणा नहीं
- जून और दिसंबर के सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनुमानित वेतन वृद्धि पर कोई घोषणा नहीं
- कम्युटेशन अवधि घटाकर 12 वर्ष करने की कोई घोषणा नहीं
- 65,70,75 बुजुर्गों के लिए 5,10,15% अतिरिक्त पेंशन पर कोई घोषणा नहीं

- **अगर देश के प्रत्येक बुजुर्ग नागरिक को 3000 रुपये गैर अंशदायी पेंशन दी जाए तो सरकार लगभग 5.36 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार चाहती है कि हम यह विश्वास करें कि हमारे बुजुर्गों पर इतना खर्च करना एक "बोझ" होगा, एक "मुफ्त" होगा। लेकिन उसी सरकार ने 2014-15 से 2022-23 के बीच बड़े कॉरपोरेट्स को लगभग 15 लाख करोड़ का राइट ऑफ दिया है।**

- बैंकों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सहमति के बिना अटल पेंशन योजना और मोदी की प्रमुख जीवन बीमा योजनाओं के लिए अवैध रूप से प्रीमियम डेबिट करने का दबाव डाला। "यह परिवार के सदस्यों को योजनाओं का लाभ लेने से रोकता है, जिससे उनका प्रीमियम भुगतान - शुरू से ही अनधिकृत - व्यर्थ हो जाता है।"

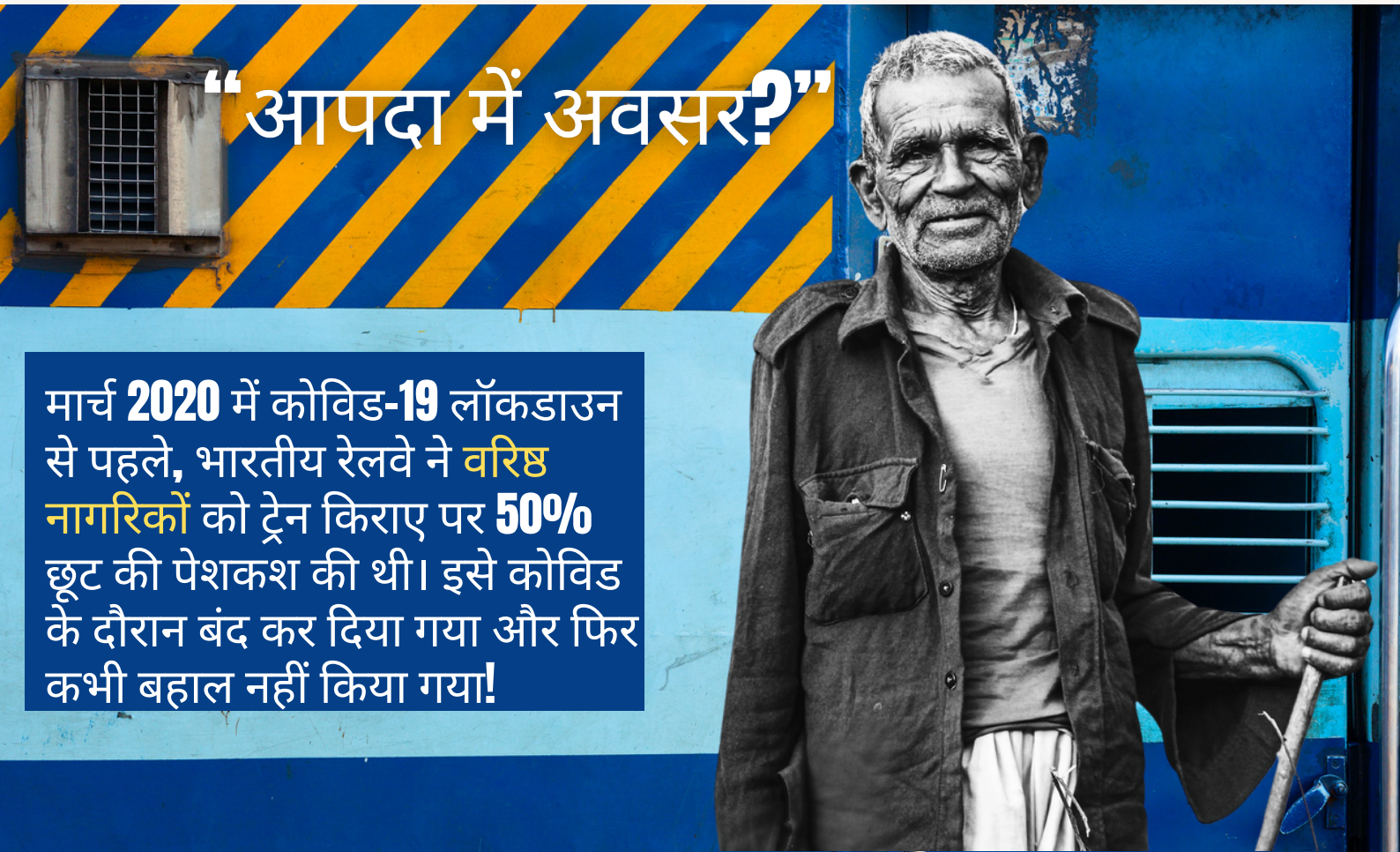

मुख्य अंश:

- एनएसएपी के तहत बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि 2007 से और विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए 2012 से स्थिर बनी हुई है।

- एनएसएपी को किया गया आवंटन भी पिछले दस वर्षों से लगभग 9500 करोड़ रुपये पर स्थिर बना हुआ है और कुल बजट के हिस्से के रूप में भारी गिरावट देखी गई है।

- एनएसएपी के तहत कड़े पात्रता मानदंड के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है। पुराने 2011 एसईसीसी डेटा, महिलाओं के लिए सख्त आयु मानदंड (40-60 वर्ष), और विकलांग व्यक्तियों के लिए नामांकन के लिए अत्यधिक उच्च विकलांगता स्तर (80% या अधिक) पर इसकी निर्भरता वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले करोड़ों लोगों को बाहर कर देती है।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध पेंशन योजनाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजनाओं के विपरीत, असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं मौजूदा कल्याण योजनाओं से जुड़ी हुई हैं और विशेष रूप से उनके लिए समर्पित नहीं हैं।

- विनिवेश से पहले एलआईसी लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में काम करती थी। अब निश्चित रूप से वैधानिक आशंकाएं हैं कि प्रीमियम का आकार बढ़ जाएगा और गरीब/ग्रामीण परिवारों का कवरेज कम हो जाएगा, जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम का चरित्र ही बदल जाएगा।

- ई-श्रम पोर्टल को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना था। हालाँकि, अभी तक 49.33 करोड़ श्रमिकों में से केवल 29.48 करोड़ ही प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत हैं।

- आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत जीडीपी का 1.4% सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य को छोड़कर) पर खर्च करता है, जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों द्वारा जीडीपी का औसतन 2.5% और उच्च-मध्यम आय वाले देशों द्वारा 8% खर्च किया जाता है।

अन्य रिपोर्ट कार्ड के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:
https://bit.ly/BSofadecade